उद्योग से सम्बन्धित 25 नवम्बर 1969, के अतारांकित प्रश्न संख्या 1222 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द ओझा) (क) जी हां,

(ख) यह सच है कि गढ़वाल के वनों की इमारती लकड़ी को इस क्षेत्र की नदियों से बहाया जाता है और उन स्थानों पर पहुंचाया जाता है जहां इसका बाजार है। जहां तक गढ़वाल में इमारती लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा समस्त पर्वतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया था। रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ गढ़वाल में इमारती लकड़ी पर आधारित कुछ उद्योगों की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए उत्सुक है और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए एक पर्वतीय विकास बोर्ड की स्थापना कर दी है। यह बोर्ड गढ़वाल सहित पर्वतीय जिलों में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के प्रकार के बारे में सिफारिश करेगा।

अलकनन्दा में बाढ़ आने के कारण हुई सम्पत्ति की हानि तथा सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

147. श्री प्रताप सिंह नेगी क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1970 में अलकनन्दा में आयी विनाशकारी बाढ़ के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा भूमि क्षतिग्रस्त हुई है ?

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा भूमि क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें कितनी सहायता देने का विचार है;

(ग) इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा यह सहायता दिये जाने का निश्चय करने में कितना समय लगेगा, और

(घ) उपर्युक्त बाढ़ के कारण गठित इस जांच समिति के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रंजनमय कुरील) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई, 1970 में अलकनन्दा की बाढ़ों के फलस्वरूप उन व्यक्तियों की संख्या, जिनकी सम्पत्ति और भूमि को क्षति पहुंची है, 11,610 है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को 1,49,100 रुपये की धनराशि पहले ही वित्तीय सहायता के रूप में दे दी है।

(घ) अलकनन्दा में बाढ़ों की जांच करने के लिए न तो केन्द्रीय सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने ही कोई समिति स्थापित की है। बहरहाल, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने जुलाई, 1970 की बाढ़ों के दौरान गंगा नहर में गाद भरने के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

Applications received from Tamil Nadu for Industrial Licences

148. SHRI S. A. MURUGANATHAM : Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT